

पड़ताल की है या कराने की कोशिश कराई जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : न की है और न कोशिश की जा रही है ।

Shri Raghuramaiah. In view of the importance of Delhi and its rapid expansion, may I know whether Government have any scheme for having a, not circular, but straight railway connecting the different parts of Delhi, preferably electrical railway running either underground or over-ground?

Mr. Deputy-Speaker: It is a suggestion for action.

Shri Raghuramaiah: No, Sir. Have they any scheme for a straight railway?

Shri Shahnawaz Khan: No.

श्री राधा रमण : अगर कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट के ब्याल में नहीं थी तो क्या कोई और तजवीज या ऐसा प्रस्ताव जिस पर आपस में बहस हुई हो ब्याल में लाया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): एक जमाना हुआ जब शायद इस बात पर गौर हुआ था कि दिल्ली में एक सरक्युलर रेलवे बनाई जाय। मगर वह बात एक कमेटी के दरज तक ही रही, उस से आगे नहीं गयी और इस वक्त मूनासिब यही मालूम होता है कि सरक्युलर रेलवे दिल्ली के लिये फ़ायदेमन्द नहीं होगी, क्योंकि उस में फ़ैलाव के लिये, ऐक्सपान्शन के लिये, जगह नहीं होगी। इस वक्त खयाल यही है कि हम बस सरबिस, ट्रांसपोर्ट सरबिस को बढ़ावें और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि ४०० बसें हमारी डी० टी० एस० में चलने लगे तो यह काम बहुत आसानी से चल सकेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ४०० बसों के मुकाबले में जो रेलवे निकाली जायगी तो उस पर ज्यादा खर्चा होगा, पेट्रोल वगैरह सब का ब्याल कर के ज्यादा खर्चा होगा ?

श्री शाहनवाज खां : हां, स़हब, उस से बहुत ज्यादा होगा, छः गुना ज्यादा होगा ।

श्री नबल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जो अगला प्लान बनेगा, पंच वर्षीय योजना बनेगी, उस में इस पर विचार करेंगे ?

श्री राधा रमण : क्या मैं मंत्री जी से यह पूछ सकता हूँ कि कलकत्ते में जो सरक्युलर रेलवे बनाने की आयोजना थी वह हाथ में है और उस की वजह से इस रेलवे के विचार को स्थगित कर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं कलकत्ते की सरक्युलर रेलवे के साथ इस का कोई ताल्लुक नहीं है । एक सेंट्रल कोआर्डिनेशन कमेटी बक्स, माइन्स, पावर मिनिस्ट्री के तहत में बनी थी । उस कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि सरक्युलर रेलवे की दिल्ली में जरूरत नहीं है, और दिल्ली की ट्रांसपोर्ट प्राबलम को हल करने के लिये पहले तो बस सरबिस में बसों की तादाद ४०० तक बढ़ाई जाय और फिर ट्रांली इलैक्ट्रिक बसों के तीर पर चलाई जाय ।

श्री राधा रमण : क्या मैं मंत्री जी से यह पता लगा सकता हूँ कि उन की यह योजना ४०० बसों की दिल्ली के चारों तरफ़ ट्रांसपोर्टेशन के सवाल को हल करने के लिये कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह जो तहकीकात की गयी है उस से पता चला है कि ४०० बसें चलाने से दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट प्राबलम है व हल हो सकती है ।

COST OF PRODUCTION OF FOOD CROPS

*1144. **Shri Madiah Gowda:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the cost of production of any of the food crops, has been enquired into; and

(b) If no enquiry is made, whether any reasons can be assigned for the same?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): (a) No cost of production enquiry has yet been conducted by the Government of India, except for some pilot surveys.

(b) I place a note on the Table of the House showing what has been attempted and what the difficulties have been. [See Appendix VIII, annexure No. 9.]

Shri Madiah Gowda: From the statement laid on the Table of the House, I find that a number of piecemeal schemes were framed from 1944 and none of them was successful. May I know whether Government now consider it possible for them to formulate a comprehensive scheme for a cost of production enquiry and give effect to it?

Dr. P. S. Deshmukh: The note mentions all the difficulties facing us. There is no proposal at the moment to undertake this work on such a large scale.

Shri Madiah Gowda: What basis do Government have now for formulating policies relating to food and agriculture in the absence of a definite cost of production enquiry regarding even important crops like paddy, jowar, wheat, ragi etc.?

Dr. P. S. Deshmukh: Now and again attempts are made not only by the Government of India under the I.C.A.R. schemes, but the State Governments also have their own schemes, and we have some rough approximation before us which guides us in fixing the prices and arriving at policies.

Shrimati Renu Chakravartty: May I know on what basis the procurement price of food has been worked out in the absence of cost of production figures?

Dr. P. S. Deshmukh: There is no total absence of data of cost of production. As I said, there is an approximate cost of production which we go by.

Shrimati Renu Chakravartty: May I know how that has been worked out?

Dr. P. S. Deshmukh: I cannot describe the method of arriving at it.

Shri Shivananjappa: Has any similar survey been made regarding commercial crops?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member behind him, Mr. Chinaria.

Shri Chinaria: May I know whether the demonstration farms run by Government can help in arriving at the cost?

Dr. P. S. Deshmukh: Yes. Their figures and calculations are often taken into account.

श्री धुलेकर: आपने कहा कि जो स्टेटमेंट रक्खा है उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं तो क्या मैं जान सकता हूँ कि उस इन्क्वायरी के लिए खासकर कठिनाइयां क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: सरसरी तौर पर तो मैं बहुत सारी बतला सकता हूँ। एक तो यह है कि हर एक खेत और काश्तकार में बहुत फर्क है एक खेत के लिये जो कंडीशन हैं वह दूसरी खेत में नहीं मिलती। इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हमारे सामने पेश हैं।

Shri Achuthan: Are we to understand that procurement price of paddy in Uttar Pradesh is double that of Orissa, Madhya Pradesh and some other States, in spite of the lack of means of ascertaining the cost of production, because U.P. is imposing U.P. and Orissa, poor Orissa?

Mr. Deputy-Speaker: All these insinuations need not be made. Straight questions may be asked and information elicited.

Dr. P. S. Deshmukh: Mere cost of production is not the determining factor. We have to take into consideration other factors for fixing the procurement price—the economy and recommendations of the State Government, themselves included.

LIQUIDATION OF CLAIMS ON RAILWAYS

*1145. **Shri K. C. Sodhia:** (a) Will the Minister of Railways be pleased to state what steps Government have taken to liquidate the claims on those Railway Receipts in regard to which goods were not allowed to be transported from West Pakistan after partition and were not received by the consignees?

(b) What was the total value of such claims?